उद्योगों से प्रदूषण रोकने को कार्ययोजना तैयार

■ अजित खरे

लखनऊ। यूपी सरकार ने उद्योगों से होने वाले प्रदूषण रोकने को छह साल का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस प्रदूषणकारी ईंट- भट्टा उद्योग के सुधार पर किया जाएगा। इसका पूरी तरह कायाकल्प कर आधुनिक तकनीक से ईंट व अन्य भवन निर्माण सामग्री बनाने काम शुरू होगा। इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि इस उद्योग से प्रदूषण उत्सर्जन रोका जा सके। यूपी सरकार ने अगले छह साल के लिए यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट परियोजना तैयार की है। इसे जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी।

उत्सर्जन निगरानी केंद्र

पूरे राज्य में पहले प्रदूषण से प्रभावित औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित होंगे। इससे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सहयोग करेगा। इसके बाद एयर एक्शन प्लान लागू होगा। इसके अलावा औद्योगिक कलस्टर में 1000 सीईएमई (सतत उत्सर्जन निगरानी केंद्र) की स्थापना होगी। इसके अलावा छह बड़े औद्योगिक गलियारों में सीईएम लैब भी बनेगी।

योजना की खास बातें

राज्य में 11838 ईंट भट्टा हैं। इसमें केवल 13 प्रतिशत ने ही प्रदूषण रोकने को क्लीनर जिगजैग तकनीक अपनाई है। इसे अपनाने पर ईंट भट्टा वालों को इंसेंटिव देने की तैयारी है। मार्च 2026 तक 40 प्रतिशत ईंट भट्ठा क्लीनर जिगजैग तकनीक आधारित हो जाएंगे। चार साल बाद सभी ईंट भट्टे नईतकनीक पर आधारित हो जाएंगे।

इसके तहत साल 2030 तक इसे पूरी तरह लागू करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग ने कार्य योजना बना ली है। इसमें आधुनिक तरीके से ईंट निर्माण योजना शामिल है। पहले दो साल में इस बदलाव पर 30400 लाख रुपये खर्च करने की योजना है। इसके अलावा टनल क्लिन मैन्यूफैक्चरिंग पर भी काम होगा। क्लिन आपरेटर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार रिसोर्स इफीसिएंट ब्रिक (आरईबी) बनाने के लिए ईंट भटटा निर्माताओं को कैपिटल सब्सिडी की सुविधा देगी।

उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषण रोकने को औद्योगिक विकास, एमसएसएमई, यूपीसीडा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व औद्योगिक संगठन मिल कर करेंगे। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी ईकाईयां (ईट भट्टा, निर्माण कार्य,कपड़ा, चर्म, प्लास्टिक उद्योग) आदि एमएसएमई सेक्टर में हैं। इसके बाद प्रदूषण बढ़ाने में बड़े उद्योगों यानी आयरन स्टील, सीमेंट व पावर प्लांट का नंबर आता है।